

शहरी विकास का दृढ़ इरादा, भाजपा का आपसे वादा



नगरीय निकाय चुनाव 2019
संकल्प पत्र



भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़



प्रिय मतदाता भाईयों एवं बहनों,

छत्तीसगढ़ के शहरों का विकास दशकों से थमा हुआ था। भाजपा की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में इस अवरोध को न सिर्फ तोड़ा बल्कि नई सोच तथा बड़े निर्णयों के साथ छत्तीसगढ़ के शहरों के चौतरफा विकास को गति दी थी। किन्तु प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही विकास की गति पूरी तरह थम सी गयी है।

अतः एक बार फिर से शहरी विकास को गति देने हम आप से सहयोग मांगने आ रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में प्रदेश के शहरों में हुए विकास कार्यों को देखा है, परखा है और अनुभव किया है। प्रदेश में शांति व समृद्धि का जो वातावरण था उसमें अब ग्रहण लग गया है। शहरी आदमी के चेहरे का मुस्कान छिन गया है। उम्मीद है आप इस मुस्कान को बनाये रखने में अपना बहुमूल्य सहयोग देते हुए भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाकर शहर के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान देंगे।

आपका ही
विक्रम उसेंडी
प्रदेश अध्यक्ष
भाजपा, छत्तीसगढ़



नगरीय निकाय चुनाव 2019

संकल्प पत्र

चुनाव घोषणा पत्र समिति

- ❁ श्री बृजमोहन अग्रवाल, संयोजक
- ❁ श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य
- ❁ श्री अमर अग्रवाल, सदस्य
- ❁ श्री सुनील सोनी, सदस्य
- ❁ श्री मधुसूदन यादव, सदस्य
- ❁ श्री किरण देव, सदस्य
- ❁ श्री संजय श्रीवास्तव, सदस्य
- ❁ श्री प्रबोध मिंज, सदस्य
- ❁ श्री किशोर राय, सदस्य
- ❁ श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर, सदस्य
- ❁ श्री ओ.पी. चौधरी, सदस्य
- ❁ श्री जोगेश लाम्बा, सदस्य
- ❁ श्री बुगल दुबे, सदस्य
- ❁ श्री श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती, सदस्य



2 वोट के अधिकार को छीनने वालों पर करनी है चोट



जनता के 2 वोट के अधिकार को छीनने वाली कांग्रेस पर... अपने 1 वोट से करनी है चोट। नगरीय निकाय चुनाव में जनता को दो वोट का अधिकार था। एक वोट पार्षद के लिए और दूसरा वोट मेयर/अध्यक्ष के लिए। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जनता के इस अधिकार को छीन लिया है। कांग्रेस सरकार ने आपका हक छीना है। अब अपने एक वोट से चोट करके कांग्रेस को सबक सिखाना है।

- **भाजपा को वोट देकर विकासशून्य** कांग्रेस सरकार को जवाब देना है, जिसने पूरे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विकास को ठप्प कर दिया है। पूर्व भाजपा सरकार के समय स्वीकृत सारे कार्य निरस्त कर दिए गये हैं और कोई नया विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। अपना वोट भाजपा को देकर कांग्रेस को चोट करें ताकि निरंकुश कांग्रेस सरकार जागे।
- **डिजिटल होते भारत को वापिस पीछे धकेल** कर ई.वी.एम. सिस्टम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले कांग्रेस सरकार को जवाब देना है।



संकल्प पत्र के प्रमुख बिन्दु हमर 36गढ़ के शहर मन के विकास बर 36 परयास...

1. कांग्रेस के घोषणापत्र में प्रॉपर्टी टैक्स को आधा करने का वादा किया गया है, लेकिन 2018–19 एवं 2019–20 में प्रॉपर्टी टैक्स में कोई छूट नहीं दी गयी है। इसकी भरपाई करने की एक कोशिश के रूप में **भाजपा 2020–21 का पूरा प्रॉपर्टी टैक्स माफ हो इसलिए पहल करेगी।**
2. मान. श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन अनुरूप 2015 से शहरों में निवासरत, 3 लाख से कम आय वाले परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु कोशिश करेंगे। साथ ही **प्रधानमंत्री आवास योजना में, वर्तमान नियमों के अंतर्गत न आने वाले परिवारों को भी योजना से जोड़ने हेतु पहल की जायेगी।**
3. “हर घर शौचालय” की तर्ज पर मोदी जी के **2024 तक “हर घर तक नल से जल”** पहुँचाने के विजन के अनुरूप पहल करेंगे।
4. महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा NULM: राष्ट्रीय “शहरी आजीविका मिशन” में महिला समूहों के खाते में निकायों द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त 10 हजार की राशी डाली जाती है, ताकि वो बैंक से लिंक हो जायें और अपना रोजगार बढ़ा सकें, **भारतीय जनता पार्टी इस राशि को दोगुना कर, 20 हजार करने हेतु पहल करेगी।**



5. स्मार्ट सेवायें (Smart Services) "सेवायें आपके मोबाइल से, आपके घर पर" CSC: कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न सेवायें प्रदाय की जा रही हैं। इससे आगे बढ़ते हुए मोबाइल ऐप (Mobile App) के माध्यम से इन सुविधाओं की घर पहुँच सेवा (Door Step Delivery) सुनिश्चित की जाएगी।
6. युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग सेंटर, नालंदा परिसर जैसे लाइब्रेरी, करियर ऐप, हाई-स्पीड वाई-फाई जोन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेगी।
7. मनचलों पर लगाम (मजनू स्पॉट्स) CCTV कैमरों से छेड़छाड़ रोकने हेतु निगरानी, महिला कमांडो द्वारा शराब कोचियाओं पर नियंत्रण, आत्मरक्षा कार्यशालाएं (Self Defense Workshops), महिला रोजगार मेले (Women Employment Fair), भ्रूण हत्या पर नियंत्रण, पृथक महिला गार्डन (Dedicated Women Garden), कामकाजी महिला हॉस्टल (Working Women Hostel) जैसे प्रयासों से समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जायेगा।
8. निगम के स्कूलों एवं निगम क्षेत्र के स्कूलों को उन्नत लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, स्मार्ट रूम, ओपन-एयर जिम, कम्युनिटी ट्युशन जैसी सुविधाओं के साथ "स्मार्ट स्कूल" (SmartSchool) के रूप में विकसित किया जायेगा।



9. नगरीय निकायों में चुने हुए जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से "हेल्प टू हेल्थ एंड वेल्थ" (Help to Health and Wealth) योजना चलाई जायेगी। इस योजना के माध्यम से नगरीय निकायों में भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सप्ताह में एक दिन डीजल-पेट्रोल युक्त वाहनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
10. योग, सेहतमंदी, संतुलित आहार आदि को प्रोत्साहित करके स्वस्थ जीवनशैली (Healthy Life Style) को सभी नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जायेगा।
11. "धूल मुक्त शहर", वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, शौचालयों का अधिकाधिक उपयोग, सामुदायिक शौचालयों, "कबाड़ से जुगाड़", डंपिंग यार्ड की व्यवस्था, बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था, हाईजेनिक मार्केट, मेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक निष्पादन, मवेशियों की उचित व्यवस्था जैसे कदमों से मोदी जी के "स्वच्छ भारत मिशन" को वास्तविक अर्थों में साकार करेंगे।
12. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट रणनीति के साथ ठोस कदम उठाये जायेंगे।
13. तालाबों का संरक्षण-संवर्धन सुनिश्चित करके एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर शहरों में भूजल स्तर को ऊपर लाने के प्रभावी प्रयास किये जायेंगे।
14. नगरीय निकायों द्वारा अंतिम संस्कार हेतु जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क लकड़ी, ताबूत उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही जरूरतमंद परिजनों को श्रद्धांजलि योजना अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा अंतिम संस्कार हेतु, पहले से प्रदाय की जा रही राशि को दोगुना कर 4 हजार रूपए प्रदान किये जायेंगे।



15. नगरीय निकायों को, "चुंगी क्षतिपूर्ति" की मिलने वाली प्रति व्यक्ति राशि को दुगनी करने की मांग सरकार के समक्ष रखी जायेगी। एवं इससे प्राप्त होने वाली **अतिरिक्त आय का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिस्सा गरीबी उपशमन के कार्य में उपयोग किया जायेगा।**
16. **अवैध कॉलोनियों का समयबद्ध ढंग से 5 सालों में, नियमितकरण सुनिश्चित किया जायेगा।** इसके साथ ही **नियमितकरण हेतु शेष बचे भवनों / दुकानों आदि सभी प्रकरणों का निराकरण 3 माह के भीतर किया जायेगा।**
17. विभिन्न स्थलों को चिन्हित करके **छोटी-छोटी दुकान या गुमटी का निर्माण किया जायेगा।** जिसमें सैलून, मोची, लांड्री, फोटोकॉपी / स्टेशनरी फल / फूल / सब्जी / डेयरी जैसी दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे।
18. वेंडर पॉलिसी अंतर्गत सभी प्रमुख शहरों में **वेंडर मार्केट का निर्माण कर फेरीवालों का व्यवसाय सुरक्षित और व्यवस्थित किया जायेगा।** फेरीवालों को पहचान पत्र और अनुज्ञा पत्र दिया जायेगा ताकि उन्हें व्यवसाय करने में कोई परेशान न करे।
19. अंबिकापुर मॉडल की तर्ज पर शहरी कूड़ा बीनने वाले (Rag Picker) को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से जोड़ते हुए उनके व्यवसाय को सुदृढ किया जायेगा।
20. **गरीब वर्ग के परिवारों को कन्या विवाह व शोक कार्यक्रम पर नगर निगम की ओर से मुफ्त पानी टैंकर की व्यवस्था की जायेगी।**



21. रेलवे ट्रैक के किनारे बसे बस्तियों के विकास के लिए भी केंद्र सरकार से आवश्यक पहल की जायेगी।
22. विभिन्न पेंशन योजनाओं के भुगतान के लिए बैंकों से सामंजस्य करके सभी हितग्राहियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्ड (Social Security Card) बनवाने की पहल की जायेगी ताकि हितग्राही अपने पेंशन मनचाहे समय पर ATM कार्ड से भी निकाल सकें।
23. प्रत्येक कार्यालयों में एक कमरे को “सूचना केंद्र” (Information Centre) के रूप में विकसित किया जायेगा, जिसमें आम लोगों को सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके।
24. “सस्ते मासिक परिवहन पास” के माध्यम से बुजुर्गों, विद्यार्थियों एवं महिलाओं को विशेष सुविधाएँ दी जायेगी।
25. वार्डों की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए पार्षद निधि में वृद्धि के लिए कदम उठाया जायेगा।
26. राजधानी की तर्ज पर विभिन्न शहरों में रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, अंडरब्रिज, ट्रांसपोर्ट नगर, थोक सब्जी बाजार, बाई-पास, सड़कें आदि विकसित करके व्यवस्थित शहरों के निर्माण की दिशा में प्रयास किया जायेगा।



27. केंद्र सरकार की "अमृत" योजनान्तर्गत, प्रथम चरण में प्रदेश के बड़े शहरों में मलजल युक्त नालों के दूषित पानी को नदी में प्रवाहित करने से पहले **STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाकर शुद्धिकरण किया जायेगा**। जैसे वर्तमान में केंद्र सरकार की "अमृत" योजना अंतर्गत, रायपुर नगर निगम में 4 STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की योजना प्रगतिरत है।
28. "सियान सदन" एवं "बापू की कुटिया" की तर्ज पर, सम्मानीय **बुजुर्गों के मेल-मिलाप, संवाद एवं मनोरंजन के लिए केंद्र विकसित किये जायेंगे**। यहाँ योग केंद्र, ओपन एयर जिम, भजन-गायन, लाइब्रेरी, संगीत जैसी सुविधाएँ होंगी। आवश्यकता अनुसार उक्त सेंटर्स तक आने-जाने के लिए बस की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।
29. **दिव्यांगों हेतु उन्नत केंद्र, वेंडर जोन में 6 प्रतिशत आरक्षण** जैसे कदमों से दिव्यांग भाई-बहनों के जीवन में बेहतरी के प्रयास किये जायेंगे।
30. **ओपन एयर जिम, स्थानीय खेलों को बढ़ावा, मैराथनों का आयोजन, आउटडोर एवं इनडोर स्टेडियम के निर्माण**, प्रशिक्षण हेतु कोच की सुविधा-जैसे कदमों से नगरीय निकायों में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया जायेगा।
31. **नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर भर्ती की पहल** की जायेगी।



32. आवारा मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए बड़े शहरों के आउटर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मार्ग पर एवं छोटे से छोटे शहरों में भी "गौ-सेवा केंद्र" निर्मित किये जायेंगे। इनके संचालन हेतु गौ-पालकों को संलग्न किया जायेगा।
33. नगरीय निकायों में जुड़े नये गाँवों के लिए "समागम अभियान" चलाया जायेगा, जिसके तहत इन नये जुड़े गाँवों में भी समान रूप से बिजली, सड़क, नाली, नल से जल जैसी सारी सुविधाएँ पहुंचाई जायेंगी।
34. शहर के मार्गों, प्रमुख भवनों, तालाबों, उद्यानों का नामकरण, स्थानीय लोगों की सलाह से राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के नाम से किया जायेगा। इसके अलावा महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना के लिए भी पहल की जायेगी। ओपन एयर थिएटर/सांस्कृतिक परिसरों/मुक्तांगन/ऑडिटोरियम का निर्माण कर छत्तीसगढ़ की लोककला, गायन, नृत्य, संस्कृति को बढ़ावा दिया जायेगा।
35. व्यंजनों को प्रोत्साहित करने के लिए "हमर चूल्हा" केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही "गढ़ कलेवा" की तर्ज पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए नये केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
36. नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों से, भाजपा "राम-जन्म भूमि" दर्शन यात्रा का आयोजन करेगी। इसके साथ ही अन्य धर्मों के लिए भी यात्रा आयोजन किये जायेंगे। इसमें विभिन्न सामाजिक-धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों को भी जोड़ा जायेगा।



- मान. श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन अनुरूप 2015 से शहरों में रहने वाले 3 लाख से कम आय वाले प्रदेश के परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु पहल करेंगे ।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्तमान नियमों के अंतर्गत नहीं आने वाले हितग्रहियों को भी लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार से पहल की जायेगी ।
- जिनकी जमीन नहीं, उन्हें मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में घर उपलब्ध करवाएंगे ।
- जिनके पास स्वयं की जमीन है, उनका "मोर जमीन मोर मकान" के अंतर्गत आवास सुनिश्चित करेंगे ।
- निजी क्षेत्र के बिल्डरों की हर कॉलोनी में 15 प्रतिशत भूखंड गरीबों के मकान हेतु आरक्षित रखना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- मकान का आवंटन महिला या महिला और पुरुष के संयुक्त नाम से किया जाएगा ।



- महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा NULM..राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में महिला समूहों के खाते में निकायों द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त 10 हजार की राशि डाली जाती है, ताकि वो बैंक से लिंक हो जायें और अपना रोजगार बढ़ा सकें, भारतीय जनता पार्टी इस राशि को 20 हजार करने हेतु केंद्र से पहल करेगी।
- शहर की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप स्किल ट्रेनिंग देकर अधिकाधिक रोजगार सृजित करेंगे।
- पोर्टल और ऐप के माध्यम से युवाओं को रोजगार स्थानों तक जोड़ने के लिए प्लेटफार्म निर्मित करेंगे।
- अधिकाधिक "प्लेसमेंट कैम्प" (Placement Camp) आयोजित करके राष्ट्रीय व स्थानीय क्षेत्रों के रोजगार प्रदाताओं को आमंत्रित कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे।
- केंद्र सरकार की योजना NULM.. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत अधिक से अधिक महिला समूहों का गठन कर योजना का लाभ प्रदान करेंगे।
- शहरी पथ विक्रेताओं को चिन्हांकित कर उक्त योजना का लाभ दिलवाया जायेगा।
- महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा NULM..राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में महिला समूहों के खाते में निकायों द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त 10 हजार की राशि डाली जाती है, ताकि वो बैंक से लिंक हो जायें और अपना रोजगार बढ़ा सकें, भारतीय जनता पार्टी इस राशि को 20 हजार करने हेतु केंद्र से पहल करेगी।



- रायपुर, नवा रायपुर (अटल नगर), बिलासपुर को त्वरित गति से विकसित कर देश के सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करेंगे ।
- प्रदेश के अन्य शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जायेगा ।
- शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जायेगा ।
- सेवा प्रदाय करने में मोबाइल गवर्नेंस की मदद से पारदर्शिता लाई जाएगी ।
- स्मार्ट सेवायें (Smart Services) :- “सेवायें आपके मोबाइल से, आपके द्वार पर” CSC--कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न सेवायें प्रदाय की जा रही हैं । इससे आगे बढ़ते हुए मोबाइल ऐप (Mobile App) के माध्यम से इन सुविधाओं की घर पहुँच सेवा (Door Step Delivery) सुनिश्चित की जाएगी ।



- PET, PMT, CLAT, एवं रेलवे, बैंकिंग, SSC जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केंद्र, नगरीय निकायों द्वारा संचालित किये जायेंगे।
- युवाओं के लिए अधिकाधिक कैरियर अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए, "कैरियर काउंसलिंग केंद्र" (Career Counseling Centre) स्थापित करेंगे।
- युवाओं में रीडिंग कल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा स्थापित "नालंदा परिसर" (Nalanda Parisar) की तर्ज पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप लाइब्रेरी विकसित करेंगे।
- "कैरियर ऐप" (Career App) विकसित करके कैरियर अवसरों की जानकारी सीधे युवाओं के मोबाइल तक पहुंचाएंगे।
- शहरों के विभिन्न स्थानों में "हाईस्पीड वाई-फाई जोन" (Hi Speed Wi-Fi Zone) स्थापित करेंगे।
- विभिन्न कॉलेजों में मूल्य परख एवं रोजगार परख व्यवस्थाओं को बढ़ावा देंगे।
- युवाओं के लिए कॉलेज में स्टार्टअप, (Start Up) स्टैंडअप (Stand Up), इंटरनशिप, उद्यमिता, गाँव में व्यावहारिक जीवन संपर्क की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जायेगा।
- नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर भर्ती की पहल की जायेगी।



- ऐप, टोलफ्री नंबर और अन्य डिजिटल माध्यमों से 24 / 7 सजगता बरतकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- 'मनचला' (मजदूरी स्पॉट्स) को चिन्हित करके CCTV कैमरे लगाकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के प्रयास किये जायेंगे।
- शहर में कांग्रेस के आने के बाद फैल रहे शराब कोचियाओं को नियंत्रित करने की पहल करके शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण करेंगे।
- अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए महिला कमांडो की नियुक्ति की जाएगी।
- घरेलू हिंसा को नियंत्रित करने के लिए "सखी सेंटर" एवं पुलिस का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
- महिलाओं के लिए आत्मरक्षा की तकनीकों को विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से "आत्मरक्षा कार्यशाला" (Self Defence Workshops) लगाई जायेंगी।
- प्रमुख शहरों में सर्वसुविधायुक्त कामकाजी महिला हॉस्टल (Working Women Hostel) बनाये जायेंगे।
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजनान्तर्गत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु अधिकाधिक दुकानों का आवंटन किया जायेगा।



- महत्वपूर्ण राशन दुकानों का संचालन महिला समूहों के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- गरीबों के लिए निर्मित आवास महिलाओं के नाम से आबंटित किये जायेंगे ।
- भारत सरकार की अधिकाधिक योजनाओं का उपयोग करते हुए अकुशल महिलाओं के लिए "महिला रोजगार मेले" (Women Employment Fair) आयोजित किये जायेंगे ।
- समाज में "चैंपियन महिलाओं" (Champion Women) को चिन्हित करके उनके माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जायेगा ।
- मोदी जी के "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" की तर्ज पर "भ्रूण हत्या" को हतोत्साहित करने के लिए जागरूकता के प्रयास किये जायेंगे ।
- बहनों के लिए "सेनेटरी पैड" को किफायती दर पर उपलब्ध करवाने के लिए स्वसहायता समूहों की ओर से प्रयास किये जायेंगे ।
- हर छोटे-बड़े शहर में माताओं-बहनों के लिए पृथक रूप से महिला उद्यानों (Women Gardens) का निर्माण किया जायेगा । इन उद्यानों में महिलाओं एवं बच्चों को ही प्रवेश दिया



- दिव्यांग कल्याण
- हमारे सम्मानीय वृद्धजन

- दिव्यांगों की शिक्षा हेतु उन्नत केन्द्रों की स्थापना की जायेगी जिसमें स्पीच थेरेपी (Speech Therapy), ब्रेल, फिजियोथेरेपी जैसी सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी।
- निराश्रित निधि का अधिकाधिक उपयोग करके कृत्रिम अंगों का एवं अन्य सहायक उपकरणों का अधिकाधिक वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा।
- प्रत्येक वेंडर जोन में न्यूनतम 6 प्रतिशत स्थान दिव्यांग भाई-बहनों के लिए आरक्षित रहेंगे।
- "सियान सदन" एवं रायपुर के "बापू की कुटिया" की तर्ज पर सम्मानीय बुजुर्गों के मेल-मिलाप, संवाद एवं मनोरंजन के लिए केंद्र विकसित किये जायेंगे। यहाँ योग केंद्र, ओपन एयर जिम, भजन-गायन, लाइब्रेरी, संगीत जैसी सुविधाएँ होंगी आवश्यकता अनुसार उक्त सेंटरों तक आने-जाने के लिए बस सुविधा भी प्रदान की जायेगी।
- अति गंभीर परिस्थितियों के लिए समाज कल्याण विभाग विभिन्न उद्योगों के सीएसआर मद आदि से सामंजस्य करते हुए "वृद्धाश्रम" की व्यवस्था की जायेगी।
- सियान सदन, बापू की कुटिया वृद्धाश्रम आदि के संचालन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- योग क्लब, लाफिंग क्लब आदि का गठन करके समाज में स्वस्थ जीवनशैली के निर्माण में बुजुर्गों की भूमिका को बढ़ाया जायेगा।
- रिटायर्ड कर्मचारी, शिक्षक, वरिष्ठ पत्रकार आदि की भूमिका बच्चों और युवाओं में मूल्यों के विकास के लिए सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायेंगे।



- निगम के स्कूलों एवं निगम क्षेत्र के स्कूलों में लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, स्मार्टरूम, इनोवेशन कार्नर विकसित करके "स्मार्ट स्कूल" (Smart School) के रूप में विकसित किया जाएगा।
- सभी स्कूलों में हुए अतिक्रमण को खत्म कर उनके खेल मैदानों को सुरक्षित किया जायेगा।
- स्कूल परिसर में वृक्षारोपण करके ओक्सीजन के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जायेगी।
- RTE के अंतर्गत महंगे प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब जरूरतमन्द बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु पहल की जाएगी।
- गरीब जरूरतमन्द बच्चों के लिए स्वयं सेवी शिक्षकों को प्रोत्साहित करके सामुदायिक कम्यूनिटी ट्यूशन (Community Tuition) की व्यवस्था करवाई जाएगी।
- सभी स्कूल परिसर में "ओपन एयर जिम" एवं "चिल्ड्रन पार्क" स्थापित किये जायेंगे।
- स्कूलों में विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था को "अक्षय पात्र" जैसी संस्थाओं का सहयोग लेकर प्रभावी बनाने हेतु पहल की जाएगी।



- भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय में चुने हुए अपने जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से “हेल्प टू हेल्थ एंड वेल्थ” (Help to Health and Wealth) योजना चलाएगी। इसके माध्यम से सप्ताह में एक दिन डीजल-पेट्रोल युक्त वाहनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य सुधार का सन्देश तो जायेगा ही साथ ही व्यक्ति के धन में भी बचत के कारण वृद्धि होगी। 21 वर्ष का एक पार्षद यदि अपने 71 वर्ष की उम्र तक यह करता है तो $50 \times 52 = 2600$ सप्ताह होते हैं जिसमें एक दिन यदि 5 लीटर पेट्रोल के हिसाब से बचत माने तो अपनी पूरी उम्र में औसतन 10 लाख रूपए से अधिक की बचत कर लेंगे।
- “सेहतमंदी” की तर्ज पर विभिन्न खेलों, जुम्बा, व्यायाम के माध्यम से पॉजिटिव उत्साहपूर्ण जीवनशैली को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- योग की संस्कृति को शहरों में बढ़ावा देकर मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जायेगा।
- संतुलित आहार के लिए सेमिनार, संगोष्ठी आदि का आयोजन किया जायेगा।
- शहरों में डॉक्टरों एवं दवा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने वाले ऐप डेवलप किये जायेंगे।



- "स्वच्छ भारत" अभियान अंतर्गत शहर में स्वच्छता सुनिश्चित करके बीमारियों को कम करने का प्रयास किया जायेगा।
- मितानिन बहनों एवं समाजसेवी संस्थाओं की मदद से संक्रामक बीमारियों को रोकने के प्रयास किये जायेंगे।
- "शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों" (Urban PHCs) की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु पहल की जायेगी।
- झुग्गी-बस्तियों में लगातार "हेल्थ कैम्प" आयोजित किये जायेंगे।
- मोदी सरकार की "आयुष्मान भारत योजना" के माध्यम से अधिकाधिक लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
- AIIMS, मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों के सामने "मंगल भवन" का निर्माण किया जायेगा जिसमें मरीज के साथ आये सहायक, सस्ते दरों पर रुक सकेंगे इनका संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा करवाया जायेगा।
- "वार्ड क्लिनिक" (Ward Clinic) प्रारंभ करने की पहल की जायेगी



- वैज्ञानिक आधार पर "कचरा प्रबंधन" (Scientific Solid Waste Management) की व्यवस्था को सभी शहरों में बेहतर एवं सुदृढ़ बनायेंगे।
- स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने हेतु "बंच ऑफ फूल्स" (Bunch Of Fool) जैसे समाजसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- शौचालयों के निर्माण के बाद बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयास किये जायेंगे।
- बाजार, पार्क जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त" सामुदायिक शौचालयों" (Community Toilets) का निर्माण किया जायेगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर अधिकाधिक पृथक "महिला शौचालयों" (Dedicated Women Toilet) का निर्माण किया जायेगा।
- शहर के भीतर स्थित डेयरियों को गोकुल नगर योजना की तर्ज पर शहर से बाहर व्यवस्थापित किया जायेगा।
- निजी होटल, ढाबे, पेट्रोल पम्प आदि सभी स्थलों पर शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित कराया जायेगा और "टॉयलेट माय राईट" (Toilet My Right) के अंतर्गत आम लोगों को इन शौचालयों के निःशुल्क उपयोग का अधिकार सुनिश्चित किया जायेगा।



- "कबाड़ से जुगाड़" पद्धति के अंतर्गत अवशिष्टों के बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा।
- छोटे-बड़े सभी शहरों के लिए चिन्हित डंपिंग यार्ड (Dumping Yard) हेतु भूमि सुरक्षित करके कचरे का बेहतर प्रबंधन किया जायेगा।
- सभी शहरों के "कंटूर मैपिंग" (Contour Mapping) के आधार पर ही नालियों का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा ताकि शहर की "उचित ड्रेनेज व्यवस्था" (Proper Drainage System) सुनिश्चित की जा सके।
- मांस मछली हेतु व्यवस्थित "हाईजेनिक मार्केट" का निर्माण किया जायेगा।
- मेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।
- आवारा स्वान एवं सुअरों की परेशानियों से मुक्त शहर का निर्माण करने की दिशा में पुरजोर प्रयास किये जायेंगे।
- आवारा मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए बड़े शहरों के आउटर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मार्ग पर एवं छोटे से छोटे शहरों में भी "गौ-सेवा केंद्र" निर्मित किये जायेंगे। इनके संचालन हेतु गौ-पालकों को संलग्न किया जायेगा।



- प्रदुषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण पर एक अतिरिक्त समिति के गठन हेतु पहल करेंगे ।
- उद्योगों में उन्नत मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देकर प्रदुषण नियंत्रण करने की दिशा में पहल की जाएगी ।
- छोटे-बड़े सभी शहरों में ऑक्सीजन का निर्माण किया जायेगा, जिनमें अधिकाधिक ओक्सीजन देने वाले बड़े पेड़ लगाये जायेंगे ।
- शमशान या मुक्तिधाम, गार्डन, स्कूल परिसर, अस्पताल परिसर, तालाबों के मेड़, सड़क किनारे एवं कॉलोनियों में देसी प्रजाति के बड़े पेड़ लगाये जायेंगे ताकि अधिकाधिक ऑक्सीजन और हरा-भरा परिवेश मिल सके ।
- पेड़ों को लगाने के साथ-साथ उनके जीवित रखने पर अधिक जोर दिया जायेगा, इसमें लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी ।
- सामाजिक संगठनों के माध्यम से कचरा-टायर आदि जलाने की गलत प्रथा को नियंत्रित किया जायेगा ।
- रेल पटरी के किनारे बसे झुग्गी-बस्तियों में "उज्ज्वला योजना" का बेहतर उपयोग कर कोयला जलाने की प्रथा को नियंत्रित किया जायेगा ।



- वाहनों की प्रदुषण जांच को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिए शहरों में अधिकाधिक "PUC सेंटर" खोलना सुनिश्चित किया जायेगा।
- ध्वनि प्रदुषण को नियंत्रित करने की पहल की जाएगी।
- श्रम विभाग की सब्सिडी एवं मुद्रा लोन का प्रयोग करते हुए शहरों में सस्ते दर पर "ई-रिक्शा" उपलब्ध कराये जायेंगे।
- सौर उर्जा (Solar Energy), बायो गैस जैसे गैर परम्परागत उर्जा (Non & Conventional Energy) को प्रोत्साहित किया जायेगा।



- छत्तीसगढ़ के शहरों को तालाबों के लिए जाना जाता है। लेकिन इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। इनके संरक्षण-संवर्धन के लिए सतत प्रयास किये जायेंगे।
- गाद से भरे तालाबों को व्यवस्थित ढंग से, सही समय पर सुखाकर, गाद को हटाया जायेगा, ताकि तालाब प्राकृतिक रूप से जीवंत रह सकें।
- मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पतालों, विद्यालयों, सरकारी भवनों आदि सभी संरचनाओं में "रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम" को जीवंत रखा जायेगा।
- नक्शा पास कराते समय "रेन वाटर हार्वेस्टिंग" के लिए पहले से जमा राशि का उपयोग करते हुए भूगर्भजल शास्त्रियों (Hydrologist) एवं 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निशियनस' की मदद से शहरों में अधिकाधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि शहरों के भूजल स्तर को गिरने से रोका जा सके।
- आवश्यकता अनुसार बड़े परिसरों में, भवन के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ-साथ पूरे परिसर की सतह पर आने वाले जल की भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी।
- नदियों, तालाबों के चारों ओर अधिकाधिक वृक्षारोपण करके उन्हें जीवंत बनाया जायेगा। गणेशपूजा, ताजिया जुलूस आदि अवसरों पर सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की जागरूकता से, जल स्रोतों के अनुकूल पदार्थों का अधिकाधिक उपयोग किया जायेगा। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी के गणेश।



श्रद्धांजली योजना

- नगरीय निकायों द्वारा अंतिम संस्कार हेतु जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क लकड़ी, ताबूत उपलब्ध कराया जायेगा।
- आवश्यकता अनुसार शहरों में नये मुक्तिधामों/कब्रिस्तानों का निर्माण किया जायेगा। वर्तमान में संचालित मुक्तिधामों/कब्रिस्तानों का उन्नयन भी किया जायेगा।
- सामाजिक संगठनों के माध्यम से अधिकाधिक निःशुल्क "स्वर्ग-रथ सेवा" प्रारंभ करने की पहल की जाएगी।
- जरूरतमंद परिजनों को श्रद्धांजलि योजना अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा अंतिम संस्कार हेतु न्यूनतम 4 हजार रुपए प्रदान किये जायेंगे।
- मुक्तिधामों के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे लाया जायेगा।
- मुक्तिधामों का विकास ऑक्सिजन के रूप में किया जायेगा।



- नगरीय निकायों को, "चुंगी क्षतिपूर्ति" की मिलने वाली प्रति व्यक्ति राशि को दुगनी करने की माँग राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी। इससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिस्सा गरीबी हटाने के कार्य में उपयोग किया जायेगा।
- अवैध कॉलोनियों का समयबद्ध ढंग से 5 सालों में, नियमितकरण सुनिश्चित किया जायेगा।
- 1,50,000 बेरोजगार युवाओं को स्किल इंडिया मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर प्लेसमेंट पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- विभिन्न स्थलों को चिन्हित करके 5 छोटी दुकान या गुमटी का निर्माण किया जायेगा। जिसमें सैलून, मोची, लांड्री, फोटोकॉपी/स्टेशनरी/फल/फूल/सब्जी/डेयरी जैसी दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे।
- वेंडर पॉलिसी अंतर्गत सभी प्रमुख शहरों में वेंडर मार्केट का निर्माण कर फेरीवालों का व्यवसाय सुरक्षित और व्यवस्थित किया जायेगा। फेरीवालों को पहचान पत्र और अनुज्ञा पत्र दिया जायेगा ताकि उन्हें व्यवसाय करने में कोई परेशान न करे।
- श्रम विभाग की सब्सिडी एवं मुद्रा लोन का प्रयोग करते हुए शहरों में सस्ते दर पर "स्मार्ट टैले" उपलब्ध कराये जायेंगे।
- राशन दुकानों के संचालन हेतु महिला स्व सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जायेगा।



- "कोर पीडीएस, मेरी मर्जी" को बढ़ावा दिया जायेगा ताकि उपभोक्ता अपने पसंद के राशन दुकान से राशन ले सकें।
- ऐसे क्षेत्र, जहां मंगल भवन नहीं हैं, वहां मांग के अनुसार मंगल भवन का निर्माण किया जायेगा, ताकि गरीबजन सस्ते एवं उचित मूल्य में अपना सामाजिक आयोजन कर सकें।
- घरों में काम करने वाली अकुशल महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर ऊँचे वेतन पर कार्य योग्य बनाया जायेगा।
- महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के विक्रय हेतु अधिकाधिक "महिला हाट" का निर्माण किया जायेगा।
- आगामी पांच वर्षों में छोटे व्यापारियों को लागत मूल्य पर गुमटी नुमा छोटी दुकान हजारों की संख्या में व्यवसाय करने हेतु आवंटित किये जायेंगे।
- नगरीय निकाय के बजट में न्यूनतम 25 प्रतिशत बजट, गरीबों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने सुरक्षित रखा जायेगा।
- नगरीय क्षेत्रों में स्वयं के श्रम से जीवन यापन करने वाले श्रमवीरों, जैसे रिक्शा चालक, कुलियों तथा हाथ ठेला खींचने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित किया जायेगा।



- अंबिकापुर मॉडल की तर्ज पर शहरी कूड़ा बीनने वाले (Rag Picker) को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से जोड़ते हुए उनके व्यवसाय को सुदृढ किया जायेगा ।
- असंगठित / संगठित मजदूरों के लिए आवास, बीमा, न्यूनतम मजदूरी, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा तथा पहचान पत्र की व्यवस्था की जाएगी । सुचारू राशन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।
- आवश्यकता अनुसार शहरों में अतिरिक्त "रैन बसेरा" संचालित किये जायेंगे ।
- गरीब वर्ग के परिवारों को कन्या विवाह व शोक कार्यक्रम पर नगर निगम की ओर से मुफ्त
- पानी टैंकर की व्यवस्था की जायेगी ।
- रेलवे ट्रैक के किनारे की बस्तियों के विकास के लिए भी केंद्र सरकार से आवश्यक पहल की जायेगी ।



- स्मार्ट गवर्नेंस
- कर्मचारी कल्याण

- **स्मार्ट सेवायें (Smart Services) :**
- "सेवायें आपके मोबाइल से, आपके द्वार पर"
- CSC.. कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न सेवायें प्रदाय की जा रही हैं। इससे आगे बढ़ते हुए मोबाइल ऐप (Mobile App) के माध्यम से इन सुविधाओं की घर पहुँच सेवा (Door Step Delivery) सुनिश्चित की जाएगी।
- भवन अनुज्ञा तथा इसकी मॉनिटरिंग ई-मोड से की जायेगी।
- कर गणना प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा तथा घर बैठे ई-मोड से कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी।
- सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत और नागरिक सेवायें शामिल की जायेंगी।
- जन शिकायत सेवा "निदान 1100" का अन्य शहरों में विस्तार किया जायेगा तथा इसमें सम्मिलित सेवाओं का विस्तार किया जायेगा।
- विभिन्न पेंशन योजनाओं के भुगतान के लिए बैंकों से सामंजस्य करके सभी हितग्राहियों के लिए "सामाजिक सुरक्षा कार्ड" (Social Security Card) बनवाने की पहल की जायेगी। ताकि हितग्राही अपने पेंशन मनचाहे समय पर ATM कार्ड से भी निकाल सकें।



- प्रत्येक वार्ड में वार्ड कार्यालयों की स्थापना की पहल की जायेगी ।
- मोहल्ला समितियों की त्रैमासिक सलाह बैठक आयोजित की जायेगी ।
- प्रत्येक कार्यालयों में एक कमरे को "सूचना केंद्र" (Information Centre) के रूप में विकसित किया जायेगा, जिसमें आम लोगों को सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके ।

कर्मचारी कल्याण

- नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की पहल की जायेगी ।
- निगम के कर्मचारियों के लिए व्यवस्थित कॉलोनियों का निर्माण किया जायेगा ।
- समयबद्ध ढंग से कर्मचारियों की पदोन्नति सुनिश्चित की जाएगी ।
- कर्मचारियों की छुट्टी, वेतन, पदोन्नति आदि को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जायेगी ।



अग्निशमन सेवा सार्वजनिक परिवहन सेवा

- अग्निशमन सेवायें, होम गार्ड—पुलिस विभाग से सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रभावी बनाई जायेगी।
- शहरों में सिटी बस सेवा को और सुदृढ़ किया जायेगा।
- बसों में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं निरुशक्तजनों के लिए सीट सुरक्षित रखी जायेगी।
- बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा/GPS/Speed, Governor/ITS आदि लगाया जायेगा।
- बस अड्डों तक पहुँचने के लिए ई-रिक्शा/टेम्पो की फीडर सेवा व्यवस्थित की जायेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए उन्नत बस शेल्टरों का निर्माण किया जायेगा।
- सिटी बसों के लिए सर्वसुविधायुक्त बस डिपो का निर्माण किया जायेगा।
- "सस्ते मासिक परिवहन पास" के माध्यम से बुजुर्गों, विद्यार्थियों एवं महिलाओं को विशेष सुविधाएँ दी जायेगी।



- वार्डों की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए पार्षद निधि में वृद्धि करने की पहल की जायेगी।
- नगरीय निकायों में जुड़े नये गाँवों के लिए "समागम अभियान" चलाया जायेगा, जिसके तहत इन नये जुड़े गाँवों में भी समान रूप से बिजली, सड़क, नाली, नल से जल जैसी सारी सुविधाएँ पहुंचाई जायेंगी।
- सभी सड़कों को "ड्रेन टू ड्रेन" निर्मित करके धूल मुक्त शहर की दिशा में आगे बढ़ा जायेगा।
- अंदरूनी से अंदरूनी सभी बस्तियों सड़क और नाली की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- बड़े शहरों में शहर के अलग-अलग छोर पर बस-अड्डों का निर्माण किया जायेगा।
- छोटे से छोटे शहर में भी सर्व-सुविधायुक्त बस-अड्डे स्थापित किये जायेंगे।
- आवश्यकता अनुसार नये "ट्रांसपोर्ट नगरों" की स्थापना की जायेगी।
- शहरों में "बाई-पास सड़कों" का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा ताकि भारी गाड़ियों से शहर के लोगों को राहत मिल सके।
- व्यवस्थित थोक बाजारों, सब्जी बाजारों की स्थापना की जायेगी।
- राजधानी की तर्ज पर विभिन्न शहरों में रेलवे ओवर ब्रिज, फ्लाई-ओवर, अंडर-ब्रिज का आवश्यकता अनुसार निर्माण किया जायेगा।
- शहरों के मास्टर प्लान अनुसार शहर की अधोसंरचना का विकास सुनिश्चित किया जायेगा।
- "अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायर सिस्टम" को बढ़ावा दिया जायेगा।
- सघन इलाकों में "मल्टीस्टोरी पार्किंग" निर्मित किये जायेंगे।



खेल संस्कृति विकास

- बड़े शहरों में कोच की व्यवस्था के साथ बड़े खेल परिसरों के निर्माण एवं विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- छोटे शहरों एवं बड़े शहरों के सभी वार्डों में छोटे-छोटे खेल सेंटर विकसित किये जायेंगे। अधिकाधिक ओपन एयर जिम का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा।
- खेल सेंटरों में ऐथलेटिक ट्रैक भी स्थापित किये जायेंगे।
- इनडोर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोच की व्यवस्था एवं इनडोर स्टेडियम तैयार किये जायेंगे।
- SAI सेंटरों की संख्या बढ़ाकर छत्तीसगढ़ में अधिक संभावना वाले खेलों के खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल एवं कोच की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- छत्तीसगढ़ी स्थानीय खेलों की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जायेगा।
- मैराथन एवं अन्य आयोजनों को शहर में बढ़ावा दिया जायेगा।



- नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों से, भाजपा "राम-जन्म भूमि" दर्शन यात्रा का आयोजन करेगी। इसके साथ ही अन्य धर्मों के लिए भी यात्रा आयोजन किये जायेंगे। इसमें विभिन्न सामाजिक-धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों को भी जोड़ा जायेगा।
- आवश्यकता अनुसार नये सामुदायिक भवनों/मंगल भवनों/आंबेडकर भवनों का निर्माण किया जायेगा।
- शहर के मार्गों, प्रमुख भवनों, तालाबों, उद्यानों का नामकरण, स्थानीय लोगों की इच्छा अनुरूप, राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के नाम से किया जायेगा।
- छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकारों/कलाकारों/पत्रकारों/महान विभूतियों की प्रतिमा स्थापना की जायेगी।
- ओपन एयर थिएटर/सांस्कृतिक परिसरों/मुक्तांगन/ऑडिटोरियम का निर्माण कर छत्तीसगढ़ की लोककला, गायन, नृत्य, संस्कृति को बढ़ावा दिया जायेगा।
- छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पहल की जायेगी।
- व्यंजनों को प्रोत्साहित करने के लिए "हमर चूल्हा" केन्द्रों की स्थापना की जाएगी, महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर इनका संचालन किया जायेगा।
- "गढ़ कलेवा" की तर्ज पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए नये केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
- दान देने की हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए "नेकी की दीवार" का निर्माण किया जायेगा।



वादाखिलाफी करने वाली कांग्रेस से जनता को न्याय दिलाने में मजबूत पहल करेंगे

- प्रॉपर्टी टैक्स को आधा करने के वादे से कांग्रेस को पीछे नहीं हटने देंगे ।
- धान का न्यूनतम 2500 रूपए दिलाने वाले उनके वादे से कांग्रेस को पीछे नहीं हटने देंगे ।
- 10 लाख बेरोजगारों को न्यूनतम 2500 रूपए प्रतिमाह देने के वादे से कांग्रेस को पीछे नहीं हटने देंगे
- शराबबंदी के अपने वादे से कांग्रेस को पीछे नहीं हटने देंगे ।
- वृद्धों को 1000 एवं 1500 रूपए पेंशन के वादे से कांग्रेस को पीछे नहीं हटने देंगे ।
- महिला समूह के ऋण माफ करने के वादे से कांग्रेस को पीछे नहीं हटने देंगे ।
- 1 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे से कांग्रेस को पीछे नहीं हटने देंगे ।
- अनियमित कर्मचारियों के नियमितकरण के वादे से कांग्रेस को पीछे नहीं हटने देंगे ।
शिक्षाकर्मियों के 2 वर्ष की सेवा के बाद संविलियन के वादे से कांग्रेस को पीछे नहीं हटने देंगे ।
- चिटफंड कंपनियों से पैसे वापिस दिलाने के वादे से कांग्रेस को पीछे नहीं हटने देंगे ।
हर आवासहीन परिवार को दो कमरों का मकान दिलाने के वादे से कांग्रेस को पीछे नहीं हटने देंगे ।



छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद 2004 में जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी तो, छः दशकों के बाद शहरों में तीव्र गति से विकास कार्य हुए। शहरी आबादी तेजी से बढ़ने के बाद भी प्रायः सभी गली मोहल्लों का सिमेंटीकरण, नाली, विद्युतिकरण, पेयजल की व्यवस्था, तालाबों का सौन्दर्यीकरण, खेल मैदानों का निर्माण, स्टेडियम, जीम, ओपन जीम, वाचनालय, ऑक्सीजन, गार्डनों का निर्माण तेजी से किया गया। प्रदेश के सभी नगरों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई। परंतु विकास और सुधार एक सतत प्रक्रिया है। हर विकास के साथ जनता की आकांक्षा भी बढ़ती है। इसलिए भाजपा का संकल्प है कि प्रत्येक नगर को प्रत्येक दृष्टि से विकसित और व्यवस्थित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

उपलब्धियों एवं विकास की विरासत तथा स्वर्णिम छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य, विकास के लिए प्रतिबद्धता, महिलाओं, युवा, बेरोजगार व गरीबों की सेवा के संकल्प को स्वीकार कर, नव निर्माण की योजनाओं, नवीन कल्पनाओं तथा प्रशासनिक सुधार एवं भ्रष्टाचार का समन करने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में आपका विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित है।

भारतीय जनता पार्टी के नगर विकास के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए व बीते कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार आपसे विनय पूर्वक आशीर्वाद एवं सहयोग की कामना करती है। स्थानीय निकायों में भाजपा के ईमानदार एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं के पास प्रशासन के सूत्र रहे, जिससे स्थानीय निकायों में विकास की गंगा निरंतर बहती रहे।

आइये हम सब मिलकर स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुविधायुक्त शहरों की संरचना के इस संकल्प में सहभागी बनें। कमल पर मुहर लगाकर विकास के इस महायज्ञ में अपनी आहुति भी अर्पित करें।

भवदीय
भारतीय जनता पार्टी, छ.ग.



सोचिये..
कांग्रेस ने महापौर का चुनाव ना करा के
जनता से उनका हक क्यों छीना ??



जब हार का डर
सताये..
कांग्रेस ऐसे
उपाय लगाये...



इस फरेबी सरकार को दें
इनके झूठ की सजा
भाजपा को दिया आपका हर वोट
हमें मजबूत करेगा ।

नगर विकास की क्या पहचान
हर वार्ड में कमल निशान ।

" भाजपा ला लाबो - शहर ला बचाबो "

सोचिये..कांग्रेस को बैलेट पेपर क्यों पसंद है..

मेरे कारण वो सरकार में आये..
मतलब मैं सही थी...!!
फिर भी नगर निगम चुनाव में
तेरा उपयोग ??
मतलब उनके इरादे गलत है...!!



भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़
कमल छाप पर मुहर लगावें, भाजपा को विजयी बनावें